Title : Regarding utility of smart meters for Mumbai

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : केंद्र सरकार ने बिजली वितरण संगठनों को आरडीएसएस योजना अर्थात रीवैम्प डेवल्पमेंट सेक्टर स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में धनराशि स्वीकृत की है। मैं मुंबई शहर का प्रतिनिधित्व करती हूँ। यह 120 साल पुरानी B.E.S.T. मुंबई नगर निगम की एक पहल है। आरडीएसएस योजना के तहत BEST को 3500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। BEST मुंबई शहर को बिजली की आपूर्ति करती है। इसे स्वचालित और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए फंडिंग उचित है1

मुंबई के लिए स्मार्ट मीटरिंग कितना जरूरी है, अगर BEST के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिजली बिल रिकवरी 99% है और बिजली लॉस 5% से कम है। दोनों नंबर पूरे देश में सर्वोत्तम हैं। बिजली लीकेज, बिजली चोरी रोकने और बिजली बिल वसूली में तेजी के लिए स्मार्ट मीटर की जरूरत है। लेकिन BEST की रिकवरी अच्छी है और बिजली लीकेज कम है, तो जरूरत न होने पर भी स्मार्ट मीटर लगाना उचित है? स्मार्ट मीटर की कीमत 13,000 रुपये है। भारत सरकार इस पर केवल 15% सब्सिडी देगी। सिंगल फेज उपभोक्ता मीटर 1300 का है। तो क्या इतना महंगा मीटर लगाना उचित है? स्मार्ट मीटर लगाने का 1800 करोड़ का ऑर्डर अडानी ग्रुप को दिया गया है। BEST के कर्मचारी स्वयं मीटर लगाने और बदलने में सक्षम हैं।

-